हिमाचल अभी अभी

Himachal ABHI ABHI

/himachal.abhiabhi @himachal_abhi

नई सोच नई खोज

प्रधान संपादक : डॉ. राजेश शर्मा साप्ताहिक

प्रेरक : स्व. पंडित बालकृष्ण शर्मा

RNI No. HPHIN/2015/68432 वर्ष 12 अंक 27 कांगड़ा। शनिवार, 05 सितंबर-11 सितंबर, 2026 www.himachalabhiabhi.com तदनुसार 20 भाद्रपद, विक्रमी संवत् 2083 कुल पृष्ठ 4 मूल्य ₹5 Postal Regn.No. DGPUR/26/24-26

कर्मचारियों-पेंशनर्स का लंबित एरियर : आर्थिक स्थिति के अनुरूप चरणबद्ध भुगतान किया जा रहा - सीएम सुक्खू

■ पंकज शर्मा

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित एरियर के भुगतान को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी के दबाव में आकर एरियर का भुगतान नहीं करेगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए बकाये का चरणबद्ध भुगतान किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ बाकी एरियर भी जारी किया जाएगा। सीएम ने कहा कि 67 साल से अधिक आयु के सभी पेंशनर्स को पूरा एरियर दिया जा चुका है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी एक साल की सेवानिवृत्ति पेंशन का पूरा एरियर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्ष 2016 से 31 मार्च 2022 तक के करीब 55 से 57 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया जा चुका है। उन्हें 20

- ❖ सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाए को रोकने के पक्ष में नहीं
- ❖ आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण, लेकिन दबाव में नहीं होगा एरियर का भुगतान
- ❖ 67 साल से अधिक आयु के सभी पेंशनर्स को पूरा एरियर दिया जा चुका
- ❖ चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी एक साल की सेवानिवृत्ति पेंशन का पूरा एरियर दिया

हजार रुपये की राशि भी दी गई है. उन्होंने कहा कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनर्स के वर्ष 2016 के बाद के एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाये को रोकने के पक्ष में नहीं है. उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार लगातार भुगतान किया जा रहा है।

सीएम ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी बंद हो चुकी है। इसके बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए हैं और उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कर्मचारियों-पेंशनर्स के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी प्राथमिकताओं पर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को करीब 47 हजार करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान मिला था, जबकि मौजूदा सरकार को करीब 17 हजार करोड़ रुपये ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान सरकार को भी उसी स्तर पर आरडीजी मिलता तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाये के भुगतान में ज्यादा मदद मिलती।

सीएम सुक्खू ने दोहराया कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को नजरअंदाज नहीं कर रही है। हालांकि, एरियर का भुगतान प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में आकर सरकार एरियर जारी नहीं करेगी। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका पूरा बकाया मिले, लेकिन इसके लिए वित्तीय संसाधनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस राशि की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं की थी और यह राशि मांगने पर नहीं, बल्कि उनके द्वारा घोषित की गई थी। सुक्खू ने कहा कि घोषणा के बावजूद अभी तक हिमाचल प्रदेश को यह 1500 करोड़ रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पीएम ने खुद इसकी घोषणा की थी तो प्रदेश को यह राशि अब तक क्यों नहीं मिली।